

आरआरटीएस दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक विकसित किया जाएगा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

कॉरिडोर के लिए अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैपिंग

आदित्य राज • गुरुग्राम

दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर विकसित करने के लिए हर स्तर पर कार्य तेज कर दिया गया है। मिट्टी की जांच के साथ-साथ अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैपिंग भी शुरू कर दी गई है। इससे पता किया जाएगा कि कहाँ पर नीचे क्या-क्या है। इससे काम करने के दौरान पाइप लाइन, टेलीफोन लाइन या बिजली लाइन डिस्टर्ब नहीं होगी। मैपिंग के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इससे जमीन के नीचे कहाँ पर क्या है, आसानी से कम से कम समय में जानकारी सामने आ जाती है। अगले 30 से 40 दिनों के भीतर यह काम पूरा किया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए नेशनल



कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) द्वारा दिल्ली से अलवर तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर विकसित किया जाना है। इसके लिए कुछ कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सबसे पहले मिट्टी की जांच शुरू की गई। अब अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैपिंग का कार्य शुरू किया गया है। दोनों कार्य संपन्न होने के बाद विधिवत रूप से निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रथम चरण में दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी (शाहजहांपुर-निमराना-बहरोड) तक कॉरिडोर विकसित किया जाना है। इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। लगभग 24 हजार करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च

किए जाएंगे। दूसरे चरण में एसएनबी से सोतानाला तक काम किया जाएगा। अंतिम चरण में अलवर तक कॉरिडोर विकसित करने की योजना है।

अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी: कॉरिडोर विकसित होने के बाद दिल्ली के सराये काले खाँ से एसएनबी की दूरी केवल 70 मिनट में तय की जा सकेगी। औसतन स्पीड 100 किलोमीटर होगी जबकि अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सभी स्टेशन पर पांच से दस मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध होगी। कॉरिडोर का काफी भाग भूमिगत होगा। बता दें कि कई वर्षों से सिस्टम विकसित करने की चर्चा चल रही है लेकिन सही मायने में पिछले दो-तीन महीने से ही प्रयास तेज किए गए हैं। बताया जाता है कि प्रथम चरण के तहत काम गुरुग्राम से ही शुरू किया जाएगा। इसे देखते हुए सभी कार्य की शुरुआत गुरुग्राम से की जा रही है।



अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैपिंग के लिए जीपीआर सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। इससे खोदाई नहीं करना पड़ता है। बिना खोदाई किए ही पता लगाया जा



सकता है कि कहाँ पर नीचे क्या है। पता चलने के बाद संबंधित विभाग को हटाने के लिए कहा जाएगा। उदाहरणस्वरूप यदि कहीं पर नीचे बिजली की लाइनें हैं तो बिजली निगम से हटाने के लिए कहा जाएगा। पूरा रूट साफ होने के बाद काम शुरू किया जाएगा ताकि एक बार काम शुरू होने के बाद बीच में रुके नहीं।

सुधीर कुमार शर्मा, मुख्य सूचना जनसंपर्क अधिकारी, एनसीआरटीसी